बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 23 ● अंकः 218 ● नई दिल्ली ● शनिवार 30 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सुबह के समय सेवाएं प्रभावित, स्टेशनों पर लगी यात्रियों की भारी भीड़

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय तक येलो लाइन के एक हिस्से पर दिल्ली मेट्रो सेवाएं शुक्रवार सुबह दफ्तर और स्कूल समय के दौरान बाधित रहीं। जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा हुई। इस दौरान स्टेशनों पर काफी संख्या में यात्रियों की भीड़ देखने को मिली। अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों के बीच ट्रेनें देरी से चल रही है, जबकि नेटवर्क के अन्य सभी मार्गों पर सामान्य सेवाएं जारी है। कई यात्रियों ने शिकायत की कि विश्वविद्यालय से जीटीबी नगर तक की यात्रा का समय, जो आमतौर पर कुछ ही मिनट का होता है, वह लगभग 50 मिनट तक बढ़ गया। कई लोगों ने कहा कि देरी के कारण उन्हें समय पर दफ्तर और स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है।

सड़कें बनी स्विमिंग पूल, कारें-बाइक डूबीं, बारिश के बाद फिर बेबस दिखी दिल्ली

सरकार ने दिल्ली को डुबोकर रख दिया- आतिशी

नई दिल्ली। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई. हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था. तेज हवाओं के साथ बारिश इतनी तेज है कि सड़कों पर पानी भर गया है. बच्चों के स्कूल जाने के समय आई तेज बारिश की वजह से कई स्कूलों में पानी भर गया, जिसकी वजह से स्कूलों ने छुट्टी कर दी. क्या दिल्ली और क्या नोएडा हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. अंडरपास तो पूरी तरह से तालाब में तब्दील दिखाई दे रहे है. देशभर में मॉनसून की बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. दिल्ली-एनसीआर में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए बारिश की चेतावनी जाहिर की थी. नोएडा के कई हिस्सों में बारिश फिलहाल बंद हो गई है. लेकिन कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अगले छह दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. 3 सितंबर तक बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. शुक्रवार को भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, जो अचानक से बरस पड़े. शुक्रवार को दोपहर और शाम को भी बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 30 अगस्त को भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है. जबकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बादल छाए रह सकते है और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. 2 और 3 सितंबर को भी छिटपुट बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश ने एक तरफ लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है. थोड़ी देर की बारिश ने ही पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों को पानी से सराबोर कर दिया है. सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है. वहीं लंबा जाम लग गया है. सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से ऑफिस आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है. दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम समेत तमाम हिस्सों से लोग ऑफिस आते-जाते है. दफ्तर जाने के समय पर तेज बारिश होने से सड़कों पर जाम लग गया है. कई लोग तो घरों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे है. दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं, जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि 6 महीने में ही भाजपा की सरकार ने दिल्ली को डुबोकर रख दिया है।

आतंकवाद के खिलाफ मानवता की जीत का स्वर्णिम अध्याय है ऑपरेशन सिंदूर : राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई का एक स्वर्णिम अध्याय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी आकाशतीर एयर डिफेंस और रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान की तारीफ की। आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका पर बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने राजस्व और लाभ सहित प्रमुख वित्तीय मानकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि तीन-चौथाई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभ कमा रहे है, और पिछले दशक के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का शुद्ध लाभ काफी बढ़ा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सार्वजनिक उद्योगों ने सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में मानक स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया अभियान की अहमियत पर कहा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। देश के रक्षा क्षेत्र का विशेष उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और भारत पर हमले के प्रयासों को विफल कर दिया। स्वदेशी आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम ने अचूक क्षमता का प्रदर्शन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने इस प्रणाली के निर्माण में योगदान दिया है। यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि नवाचार और भारत की बढ़ती तकनीकी विशेषज्ञता से राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का बड़ा योगदान है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कृषि, खनन और अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण और सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुर्मू ने आगे बताया कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिला नेताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

खतरे के निशान के करीब यमुना, प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर 204.5 मीटर के ऊपर बना हुआ है, लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने नदी के प्रवाह को तेज कर दिया है. इससे एक बार फिर से राजधानी में बाढ़ की आशंका गहरा गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है और बचाव संबंधित एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए है. जानकारी के अनुसार, यमुना का पानी कल शाम 205.33 मीटर के पार पहुंच गया था. लेकिन आज सुबह इसमें कुछ गिरावट देखने को मिला और यह खतरे के निशान के नीचे 204.67 मीटर पर बहती नजर आयी. पुराने लोहे के पुल के पास पानी का बहाव सामान्य से काफी ऊपर है, जो कई निचले इलाकों के लिए खतरे की घंटी है. जलस्तर में इस वृद्धि से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है. इसके बाद आज सुबह 5 बजे के करीब हथिनी कुंड बैराज से 74939 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो अगले 20 से 40 घंटों में दिल्ली तक पहुंच सकता है. जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. यमुना में पानी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से लगातार पानी का छोड़ा जाना है.

पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बैराज से हर घंटे हजारों क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है. सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से पानी का डिस्चार्ज 51,502 क्यूसेक रहा. जबकि वजीराबाद और ओखला बैराज से क्रमशः 34,120 क्यूसेक और 42,006 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, अगले 40 घंटों में यह पानी दिल्ली तक पहुंच जाएगा जिससे दिल्ली का जलस्तर और भी बढ़ सकता है. इसके बाद यमुना का चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है. जलस्तर के 206 मीटर पहुंचते ही प्रशासन निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करना शुरू कर देता है. प्रशासन ने बचाव दल एवं अन्य संबंधित एजेंसियों को स्टैंड-बाय मोड़ पर रखा है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. दिल्लीवासियों से अपील की जा रही है, कि वे यमुना किनारे न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. पिछले साल यमुना के जलस्तर ने 208.66 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिससे राजधानी के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे.

मुख्य न्यायाधीश ने नए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को दिलाई शपथ; जजों की कुल संख्या 34 हुई

नई दिल्ली।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शपथ दिलाई। दोनों न्यायाधीशों को 27 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। उनकी पदोन्नति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की पूर्ण कार्य क्षमता फिर से पूरी हो गई। जस्टिस जॉयमाल्या बागची के 2 अक्टूबर, 2031 को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति पंचोली अक्टूबर 2031 में मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे। उनके 3 अक्टूबर, 2031 को मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करने और 27 मई, 2033 को सेवानिवृत्त होने का अनुमान है।

कॉलेजियम के एकमत न होने की थ्योरी क्या?

इससे पहले 25 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को न्यायमूर्ति अराधे और न्यायमूर्ति पंचोली के नामों की शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी। हालांकि, कॉलेजियम सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने की सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी असहमति दर्ज की और कहा कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका के लिए प्रतिकूल होगी। शीर्ष न्यायालय की एकमात्र महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी असहमति दर्ज की थी। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी असहमति में कहा था कि उनकी नियुक्ति को आगे बढ़ने से कॉलेजियम प्रणाली की बची-खुची विश्वसनीयता खत्म हो सकती है।

जस्टिस आलोक अराधे

13 अप्रैल, 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति अराधे 12 जुलाई, 1988 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दीवानी एवं संवैधानिक, मध्यस्थता और कंपनी मामलों में वकालत की। अप्रैल 2007 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अराधे को 29 दिसंबर, 2009 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 15 फरवरी, 2011 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

कपिल मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला, हाई कोर्ट ने निचली अदालत से सुनवाई स्थगित करने का किया अनुरोध

नई दिल्ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत से दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले कथित भड़काऊ टिप्पणी के आरोपों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया, जब मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अपने पूरक आरोपपत्र में फ्लेटफॉर्म एक्स से प्राप्त पहलुओं को शामिल किया था, जिसमें मिश्रा के खाते के बारे में जानकारी थी, लेकिन पहले कोडिंग, समझ से बाहर के प्रारूप में थी। जेठमलानी ने अदालत से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया और तर्क दिया कि मामला शुक्रवार को आरोपों पर बहस के लिए निचली अदालत में सूचीबद्ध है और कार्यवाही शुरू करने से पहले अभियोजन पक्ष के लिए दस्तावेजों का एक पठनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि शहर की अदालत के 7 मार्च के आदेश के खिलाफ उनकी अपील, जिसमें कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए उन्हें जारी किए गए समन।

चिंताजनक : दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों की आयु 8.2 वर्ष घट जाएगी, शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। वायु प्रदूषण का यही स्तर रहा तो लोगों की औसत आयु 8.2 वर्ष घट जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एक्यूएलआई) रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में औसत सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5) का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देश से 20 गुना अधिक है। 2023 में शहर में पीएम 2.5 की मात्रा 111.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। यह डब्ल्यूएचओ की तय सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 22 गुना अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहरीली हवा के कारण दिल्लीवासियों की जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक कमी आई है, जो विश्व के किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक है। दिल्ली समेत सिंधु-गंगा का मैदानी क्षेत्र सबसे प्रदूषित है। यहां वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषित हवा से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की समस्या से निपटना बेहद जरूरी है। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) ने 2025 की एक्यूएलआई रिपोर्ट तैयार की गई है। उपग्रह से प्राप्त पीएम2.5 आंकड़ों के आधार पर यह वैश्विक और क्षेत्रीय प्रदूषण के स्तर और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव का आकलन करती है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उल्लंघन के कारण निर्माण व विध्वंस परियोजनाओं को बंद करने का आदेश दिया है। इसमें राज्य प्रदूषण बोर्डों से मुआवजा लगाने से पहले निरीक्षण और विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से उल्लंघन के दिनों की वास्तविक संख्या की पुष्टि करने को कहा गया था। 29 जुलाई को आयोग ने आगे निर्देश दिया कि शुल्कों की यथार्थवादी और निष्पक्ष गणना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना समर्थकों की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी विचार किया जाए।

बंगाली मुस्लिमों को बांग्लादेश भेजने के आरोप पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

नई दिल्ली। देश भर में बांग्ला भाषा बोलने वालों की धरपकड़ और उन्हें बांग्लादेश भेजने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी. यह याचिका वेस्ट बंगाल माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड नाम की संस्था और उसके अध्यक्ष समीरुल इस्लाम ने दाखिल की है. समीरुल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए भाषा के आधार पर मुस्लिम लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और देश से बाहर किया जा रहा है. केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि कुछ एनजीओ और राज्य सरकारें अवैध घुसपैठियों का समर्थन करती हैं. उन्हें नहीं सुना जाना चाहिए. मेहता ने दलील दी कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की कार्रवाई से प्रभावित है तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकता है. याचिका दाखिल करने वाली संस्था ऐसे लोगों की कोर्ट आने में सहायता करे. वह खुद याचिका दाखिल नहीं कर सकती. मेहता ने कहा कि घुसपैठ का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है. देश को सुरक्षित बनाना और नागरिकों का अधिकार घुसपैठियों तक जाने से रोकना सरकार का कर्तव्य है. इसके जवाब में भूषण ने कहा कि सरकार बंगाली मुसलमानों को हटाने का काम कर रही है. दोनों वकीलों की इस झड़प से अप्रभावित कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिका पर जवाब दाखिल करे. मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. जस्टिस सूर्य कांत ने लोगों को हिरासत में लेने से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी मांगी. जस्टिस बागची ने कहा कि पंजाब और बंगाल की भाषा और संस्कृति पड़ोसी देशों से मेल खाती है इसलिए, इस आरोप पर सरकार का जवाब आना जरूरी है कि सिर्फ बांग्ला बोलने के चलते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि हजारों लोगों को सिर्फ संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है. नागरिकता की पुष्टि हुए बिना या बांग्लादेश सरकार से बात किए बिना उन लोगों को जबरन बीएसएफ बॉर्डर के दूसरी तरफ भगा दे रही है. सॉलिसिटर जनरल ने भूषण की दलील को जंतर-मंतर में दिए जाने वाले भाषण जैसा बताया. इससे पहले 14 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 राज्यों को मामले में नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को कोर्ट ने गुजरात को भी मामले में पक्ष बना लिया.

आईआईआईटी-दिल्ली के टेक फेस्ट: भारत का उत्थान उसके युवाओं के कंधों पर टिका है- ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आईआईआईटी-दिल्ली के टेक फेस्ट ईएसवाईए में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए युवाओं से विश्वगुरु भारत के रूप में भारत के अगले अध्याय का नेतृत्व करने का उत्साहवर्धक आह्वान किया। वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की महान विरासत का उल्लेख करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि आर्यभट्ट के शून्य से लेकर चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा में प्रगति तक, और दुनिया भर के साधकों को आकर्षित करने वाले नालंदा और तक्षशिला तक, ज्ञान की यह खोज हमारे डीएनए में है। हार्वर्ड का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी नालंदा के सामने फीका पड़ जाता है। वह चिंगारी आज भी हमारे भीतर है। टेक फेस्ट को साहसिक सपनों को साकार करने का एक मंच बताते हुए, सिंधिया ने जोर देकर कहा कि भारत का उत्थान उसके युवाओं के कंधों पर टिका है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उन्होंने एआई की भूमिका दोहराते हुए कहा कि आईटी ने 40 साल पहले जो किया, एआई आज भी करेगा। हालांकि, कार्य केवल एआई का निर्माण करना नहीं है; बल्कि सभी के लिए उत्तरदायी एआई का निर्माण करना है, और इसे मानवता को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उस पर हावी होना चाहिए। मंत्री महोदय ने अग्रणी प्रौद्योगिकियों में भारत के बढ़ते नेतृत्व पर प्रकाश डाला। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ) पहले ही क्वांटम कंप्यूटिंग, टेराहर्ट्ज संचार, बायो-नैनो सिस्टम, स्वदेशी चिपसेट और एन्क्रिप्टेड राउटर जैसी 120 से अधिक भविष्य की परियोजनाओं में निवेश कर चुका है। उन्होंने 6जी में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरने और 2030 तक वैश्विक पेटेंट में कम से कम 10 प्रतिशत का योगदान देने के भारत के लक्ष्य की पुष्टि की। और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का केंद्र भारत के छात्र है। सिंधिया ने छात्रों को याद दिलाया कि भारत का उत्थान उसके सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित है हम एक ऐसा देश है जिसने कभी युद्ध नहीं छेड़ा, जो वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करता है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे भारत के लिए ऐसे समाधान तैयार करें जो सटीक कृषि की प्रतीक्षा कर रहे किसान, डिजिटल कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे और छोटे शहर में टेली-हेल्थ पर निर्भर मरीजों के लिए हों। विदेश में अध्ययन करने वाले भावी नवप्रवर्तकों को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने अपील की कि वे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर सकते है, सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में काम कर सकते है, लेकिन उन्हें स्वदेश लौटकर अपने ज्ञान, अपनी महत्वाकांक्षा को साथ लाना होगा, और प्रतिभा पलायन को प्रतिभा लाभ में बदलकर भारत को सोने की चिड़िया के रूप में पुनर्निर्मित करना होगा।

आज का दिन भारतीय संविधान के इतिहास में महत्वपूर्ण है

आज ही के दिन, 29 अगस्त 1947 को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान सभा में अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके संविधान के मसौदे को आकार देने में मदद की. भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च कानून है, जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह संविधान देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान दिवस26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व और इसके निर्माताओं के योगदान को याद करना है।

विजय कुमार भारती, संपादक, अशोका एक्सप्रेस

जियो-पॉलिटिकल लव ट्रेंगल : क्या एक रूस, एक भारत और एक चीन के स्वप्न से बनेगी बात?

कमलेश पांडे

आज दिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच जियो-पॉलिटिकल लव ट्रेंगल के दृष्टिगत एक रूस, एक भारत और एक चीन के अपेक्षित स्वप्न यह प्रश्न समुपस्थित है। देखा जाए तो प्रथम-द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रणेता रहे अमेरिका-यूरोप की कुत्सित नीतियों के प्रतिरोध स्वरूप बना रहे यूरेशियाई ब्लॉक यानी रूस-चीन-भारत के समूह और उसके प्रस्तावित आरआईसी त्रिकोण के सम्मुख यह मौलिक सवाल समुपस्थित है कि क्या इस त्रिकोण के बिना उनके विश्वव्यापी भविष्य और उनकी सफलता दोनों संदिग्ध रहेंगी। ऐसा इसलिए कि वर्तमान अमेरिकी सनक और हनक के प्रतिक्रिया स्वरूप अब भारत ने गुटनिरपेक्षता के बजाए रूस के साथ चीन की ओर जिस तरह से अपना झुकाव प्रदर्शित किया है, वह अमेरिका-यूरोप के मिजाज समझ और उन पर आधारित तिकड़मों को तो करारा जवाब है ही, साथ ही भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों से इतर भी एक नया और ठोस संकेत दे रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। मसलन, यह कि अपने दूरगामी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भारत किसी भी विकसित देश के पिछलग्गू में नहीं आएगा और इसकी भरपाई के लिए घोर शत्रु से भी हाथ मिलाने में नहीं हिचकिचाएगा। अमेरिका यदि पाकिस्तान-बंगलादेश को भारत के खिलाफ भड़काएगा तो भारत भी अब चुप नहीं रहेगा, बल्कि आक्रामक रणनीतिक फलस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर की भांति करेगा। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका और दो दर्जन देशों से अधिक की सदस्यता वाले यूरोपीय संघ में शामिल नाटो देशों के अंतरराष्ट्रीय तिकड़मों से निपटने के लिए जरूरी है कि रूस, भारत, चीन तीनों अपना-अपना विस्तार करें। खुद की उम्मीद से ज्यादा मजबूत बनाएं। इस दृष्टि से भारत के सदाबहार दोस्त सोवियत संघ में शामिल रहे रूस और अब चौदह देशों के अलावा, तुर्किये, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब आदि के उसमें मिलने से ही एक वृहत रूस या रूसी परिसंघ का सपना पूरा होगा। लिहाजा इस क्षेत्र में नाटो की बढ़ती दखल से भविष्य में मामले उलझ सकते हैं। इसी प्रकार भारत को उसके पड़ोसी देशों, यथा- पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, मालदीव के अलावा भी थाईलैंड, कम्बोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों को भारत में मिलाने के नैतिक प्रयत्न जारी रखने होंगे, क्योंकि इसमें ही एक वृहत भारत का सपना पूरा होगा। वहीं, इस क्षेत्र में अमेरिका या चीन के बढ़ते दखल से भविष्य में मामले उलझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से चीन के विस्तार के लिए ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, लाओस, वियतनाम आदि देशों को उसमें मिलाना जरूरी है, जिससे एक चीन का सपना जल्द पूरा होगा। लेकिन यहां पर भी अमेरिका या जापान के बढ़ते दखल से भविष्य में मामले उलझ सकते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो ये तीनों इतने वृहत भौगोलिक पॉलिटिकल ब्लॉक हैं, जिन पर रूस, भारत और चीन की पकड़ मजबूत होने से उनके संयुक्त रणनीतिक एजेंडे को बल मिलेगा। इसलिए यदि इनके एजेंडे में यह विषय शामिल नहीं है तो अविलंब कर लीजिए। इससे तीनों देशों का ही भला होगा। लेकिन एक-दूसरे के भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य हितों का सम्मान कीजिए, अन्यथा मित्रतापूर्ण भाव कटुता में तब्दील हो जाएंगी। लिहाजा यदि संभव हो तो इसी आधार पर अपनी रणनीतिक समझदारी भी विकसित कर लीजिए और एक-दूसरे के पैर को खींचना बंद कर दीजिए। यदि आप तीनों ऐसा कर पाए तो नाटो या जी-7 पर एससीओ या ब्रिक्स देश समूह चौबीस घण्टे भारी पड़ेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए पुतिन, मोदी और जिनपिंग को थोड़ा बहुत त्याग करना होगा, थोड़ा दिल बड़ा करके पड़ोसियों की मानसिकता को बदलना या जीतना होगा, थोड़ा धैर्य पूर्वक कदम बढ़ाना होगा। वहीं, निकट भविष्य में यदि भारत-रूस के प्रभावक्षेत्र इजरायल का भी इस त्रिकोण को साथ मिल गया तो यह सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी। इससे अरब व यूरोप के उन हिस्सों पर भी भारत-रूस की पकड़ मजबूत होगी, जिन पर इजरायल की धाक जमेगी। यदि यह यरुशलम-ईस्टैंड एक्सप्रेस-वे विकसित कर लेता है तो यह उसके लिए बहुत सुकून की बात होगी। यह स्थिति अमेरिका-रूस दोनों के लिए सुखद होगी। यदि इस नजरिए से नई दिल्ली-मॉस्को एक्सप्रेस-वे और नई दिल्ली-बीजिंग एक्सप्रेस-वे, नई दिल्ली-सिंगापुर एक्सप्रेस-वे और नई दिल्ली-यरुशलम एक्सप्रेस-वे बना दिया जाए तो इससे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से रूस के मास्को-बीजिंग एक्सप्रेस-वे, मास्को-इस्ताम्बुल (तुर्किये) एक्सप्रेस-वे, मास्को-बर्लिन एक्सप्रेस-वे, मास्को-पेरिस एक्सप्रेस-वे के सपने देखे जाएं तो यह उसके लिए बेहतर हो सकता है। यही बात चीन को तो उसके लिए बीजिंग-इस्ताम्बुल (तुर्किये) एक्सप्रेस-वे, टोकियो एक्सप्रेस-वे-बंदर वे, चीन-लाओस एक्सप्रेस-वे से उसके कारोबार में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा करना आसान है? जवाब होगा- शायद हां भी और नहीं भी। आज जिस तरह से अरब मुल्कों पर वर्चस्व को लेकर, भारतीय उपमहाद्वीप में वर्चस्व को लेकर, दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व को लेकर, हिन्द महासागर में वर्चस्व को लेकर, यूक्रेन में वर्चस्व को लेकर, तिब्बत पर वर्चस्व को लेकर, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में वर्चस्व को लेकर अमेरिका-यूरोप और रूस-चीन के बीच तलवारें खींची रहती हैं, शह-मात के खेल चलते रहते हैं, उसके दृष्टिगत अब भारत का साथ रूस-चीन को मिलने के संकेत भर से अमेरिका और उसके यूरोपीय समर्थक देशों की परेशानी बढ़ गई है। समझा जाता है कि अब रूस-भारत-चीन का प्रस्तावित त्रिकोण ही अमेरिका-यूरोप के देशों की उनकी लक्ष्मण रेखा बताएगा, ताकि एशिया-यूरोप में हथियार व गोला-बारूद खपाने को लेकर उनकी जो शातिर व भड़काऊ नीतियां हैं, वह बदली जा सकें। इस बारे में अब नए सिरे से उन्हें समझाना होगा और जब वे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर उसकी काट भी निकालनी होगी। दरअसल, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत हुई थी तो इसी क्रम में 'एक-चीन' नीति से संबंधित बात भी उठी थी। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री ने दावा किया कि भारत ने ताइवान को चीन का अंग मान लिया है। फिर भारत के विदेश मंत्री ने उनकी कथित टिप्पणियों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। इस पर चीन ने 'आश्चर्य' व्यक्त किया है। क्योंकि भारत ने कहा था कि ताइवान पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और उसके साथ भारत नयी दिल्ली के संबंध आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक पहलुओं पर केंद्रित हैं। मैं समझता हूं कि जयशंकर ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि अभी तो मित्रता की पुनः शुरुआत हो रही है, जिसकी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है और फिर जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पीओके, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, बंगलादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव से जुड़े मामलों पर जब चीन के स्टैंड भारत के हितों के अनुकूल होंगे तो भारत भी उसके हितों का ख्याल रखेगा। यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि, ''हम भारत के स्पष्टीकरण से हैरान हैं।'' वह जयशंकर की टिप्पणियों वाली भारत के स्पष्टीकरण की खबरों पर चीन के आधिकारिक मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रही थीं। दरअसल, यह स्पष्टीकरण भी तब आया जब चीनी विदेश मंत्रालय ने वांग के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर के बयान को गलत तरीके से उद्धृत करते हुए कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीनी प्रवक्ता ने दावा किया कि बीजिंग इस स्पष्टीकरण को 'तथ्यों के साथ असंगत' पाता है। ऐसा लगता है कि भारत में कुछ लोगों ने ताइवान के मुद्दे पर चीन की संप्रभुता को कमजोर करने और चीन-भारत संबंधों में सुधार को बाधित करने की कोशिश की है। चीन इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान चीन के भूभाग का एक अविभाज्य हिस्सा है। भारत सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस पर व्यापक सहमति है। चीन को उम्मीद है कि भारत 'एक-चीन' के सिद्धांत का गंभीरता से पालन करेगा, संवेदनशील मुद्दों को उचित ढंग से संभालेगा और द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास को बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे वांग ने गत 18 अगस्त 2025 को जयशंकर के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी पक्ष ने ताइवान का मुद्दा उठाया था।

सम्पादकीय...

कचहरी से संसद तक

उज्ज्वल निकम की जिंदगी का रुख बदलने वाली दो अहम फोन कॉल, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और दूसरी मुंबई पुलिस से। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ फोन किया बल्कि यह भी पूछा कि उनसे मराठी में बात करें या हिंदी में। इसके बाद हुई पूरी बातचीत मराठी में रही। जिसे लेकर निकम का कहना है कि 'प्रधानमंत्री मराठी बेहद धारा प्रवाह बोलते हैं।' एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने निकम के कानूनी करियर की सराहना करते हुए लिखा कि उन्होंने आम नागरिकों के न्याय और गरिमा को मजबूती दी है। मोदी ने कहा-श्री उज्ज्वल निकम की कानून और संविधान के प्रति निष्ठा मिसाल है। वह न केवल सफल वकील रहे हैं बल्कि कई अहम मामलों में न्याय दिलाने की लड़ाई की अगली पंक्ति में खड़े रहे हैं। यह कोई पुराना नाता नहीं है। उज्ज्वल निकम की प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात 2024 में हुई, जब वे लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी थे। निकम ने कहा-मैं मोदी जी के भाषणों से प्रभावित रहा हूं। वे सच्चे देशभक्त हैं और आम लोगों के मन में भी देशभक्ति भर सकते हैं। इसी कारण मैंने भाजपा ज्वाइन कर चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव वे हार गए। राज्य भाजपा इकाई ने उन्हें मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा था, जहां कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने उन्हें 16 हजार से अधिक वोटों से पराजित कर दिया। साल 2025 में निकम को राज्यसभा के लिए नामित किया गया एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी को दिशा बदल दी। एक समय के चर्चित विशेष लोक अभियोजक अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। अपने नामांकन पर निकम का कहना है कि 'भगवान की कृपा है।' हालांकि विपक्ष ने इस नामांकन को लेकर तीखा हमला किया? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह नियुक्ति दिखाती है कि सत्ताधारी दल-संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहा है। निकम ने भाजपा के लिए परोक्ष रूप से काम किया और अब उन्हें इनाम दिया गया। इन आरोपों को खारिज करते हुए निकम ने कहा कि उनका नामांकन राष्ट्रपति कोटे से हुआ है और यह साबित करता है कि वे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं हैं। उज्ज्वल निकम के नामांकन पर सवाल उठाना अनुचित है। भाजपा से उनके संबंध हो सकते हैं लेकिन इससे उनकी दक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बतौर लोक अभियोजक उनका रिकॉर्ड बेजोड़ रहा है। 1991 के कल्याण ब्लास्ट से उनकी पहली बड़ी कानूनी पारी शुरू हुई लेकिन उन्हें असली पहचान दिलाई मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने। इसके बाद 2003 के गेट-वे-ऑफ इंडिया और जवेरी बाजार जुड़वां धमाके, संगीत जगत के दिग्गज गुलशन कुमार की हत्या, 2024 में उनके कथित हत्यारे संगीतकार नदीम के लंदन से प्रत्यर्पण का मामला, 2006 का खैरलांजी दलित नरसंहार और 2013 का शक्ति मिल्स गैंगरेप केस, ये सभी मुकदमे सुर्खियों में रहे और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजे। निकम की साख ऐसी थी कि कई मामलों में पीड़ित पक्ष और उनके परिजन खुद उनसे पैरवी करने की मांग करते थे। ताजा उदाहरण दिसंबर में बीड के सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या का है, जब परिवार ने विशेष लोक अभियोजक के तौर पर निकम की नियुक्ति पर जोर दिया। विडंबना यह रही कि इस हत्या में गिरफ्तार मुख्य आरोपी कथित तौर पर एक भाजपा मंत्री का करीबी था, जिन्हें बाद में जनआक्रोश के चलते इस्तीफा देना पड़ा। उज्ज्वल निकम की जिंदगी की दास्तान उतनी ही रोचक है जितनी प्रेरणादायी। महाराष्ट्र के जलगांव से ताल्लुक रखने वाले निकम का सपना था कि लोगों के बीच अपने नाम का 'खौफ' पैदा करें। एक घटना ने उनके सोचने के तरीके को बदल दिया और आज भी उन्हें विचलित करती है। वकील के तौर पर वे शुरुआत में सहकारी संस्थाओं के मामलों की पैरवी करते थे लेकिन एक राजनीतिक ताकतवर हस्तक्षेप ने उन्हें अपराध मामलों की ओर मोड़ दिया। हुआ यूं कि एक नगरसेवक, जिस पर दिनदहाड़े एक निर्दोष की हत्या का आरोप था, को अदालत से जमानत मिल गई। निकम के लिए यह गहरा झटका था। उनके अनुसार, 'उस नगरसेवक के राजनीतिक रिश्ते थे और यही वजह थी कि उसे जमानत मिली।' निकम ने न केवल उस जमानत को रद्द करवाया, बल्कि इसी घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि अब से वे अपराधियों के खिलाफ मुकदमे लड़ेंगे। उनके शब्दों में 'मैं चाहता था कि अपराधियों के मन में मेरे नाम का डर बैठे।' आज हालात यह है कि किसी भी हाई-प्रोफाइल केस का जिक्र हो और उस पर उज्ज्वल निकम की छाप न हो, ऐसा सोचना भी मुश्किल है। अब तक वे 30 से ज्यादा फांसी की सजाओं और 600 उम्रकैद की सजाओं का श्रेय अपने नाम कर चुके हैं। महाराष्ट्र में किसी भी बड़े अपराध की घटना के बाद पीड़ित परिवारों की पहली मांग होती है उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया जाए। खुद को वे मजाकिया अंदाज में 'राज्य सरकार का एंटीबायोटिक' कहते हैं। सच यह है कि जब भी किसी मामले पर जनाक्रोश भड़कता है, निकम की नियुक्ति अक्सर हालात को शांत कर देती है। 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले निकम राज्य सरकारों और नेताओं के सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले अभियोजक रहे हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। छोटे कस्बे से वकालत की शुरुआत करने वाले निकम का मुंबई और फिर दिल्ली तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। 1993 में मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस का फोन आया, निकम के लिए यह अप्रत्याशित था। उनके मन में सवाल उठा 'क्यों मैंने मां से यह जिक्र किया, उन्होंने घबराकर कहा-मत जाना, तुम्हें मार डालेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुकी उनकी मां की यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी, मगर बेटे की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता स्वाभाविक थी। हनुमान जयंती के दिन जन्मे निकम का परिचय हमेशा निर्भीकता से रहा। अंततः वे मुंबई पहुंचे और वहां राज्य पुलिस से मिले, जिनकी कार्यशैली को वे 'स्कॉटलैंड यार्ड' जैसी मानते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों की पहली प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी। निकम के शब्दों में, एक दुबला-पतला लड़का, छोटे कस्बे से आया है, गुमसुम सा दिखता है, ये क्या करेगा।

इलेक्ट्रिक कारों से बदलेगा ऑटोमोबाइल बाजार का खेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति सुजुकी मोटर के हाईब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया और मारुति सुजुकी की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक एसयूवी, ई-विटारा के एक्सपोर्ट को हरी झंडी दिखाई। यह मॉडल भारत में बनाया जाएगा और यूरोपीय देशों और जापान जैसे प्रमुख बाजारों सहित 100 से ज्यादा देशों में भेजा जाएगा। दुनिया में पैट्रोल और डीजल की महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में लोगों द्वारा दूसरा विकल्प खोजना स्वाभाविक ही है। इस वजह से दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की दिलचस्पी भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है। लोगों की इसी रुची को देखते हुए कई कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने में लग गई है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार के लिए तैयार है। दरअसल, सरकार की तरफ से एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है। इसी नीति के चलते मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां अलग-अलग सेगमेंट में ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी बिक्री का हिस्सा हासिल करना है। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ और एमजी आने वाले सालों में ईवी क्षेत्र में प्रवेश करने या अपने मौजूदा ईवी प्रोडक्ट लाइनअप को एक्सटेंड करने की तैयारी कर रही है। आजकल हर जगह यही चर्चा है कि इलेक्ट्रिक कारों की बाढ़ ने बाजार का रुख बदल दिया है लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ गाड़ियों तक सीमित रहेगा या फिर पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बदल जाएगा?क्या डीजल-पैट्रोल गाड़ियां सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएंगी या फिर ऑटोमोबाइल की दुनिया में कोई और बड़ा बदलाव आने वाला है? 2025 में भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने नया मुकाम छू लिया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की पहली तिमाही में देश में 35,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बिकीं। 2023 में पूरे साल 82,000 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थीं, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 1,10,748 तक पहुंच गया है। यह कुल कार बिक्री का लगभग 4.5 प्रतिशत हिस्सा है। अप्रैल 2025 में टाटा मोटर्स ने 4,436 इलेक्ट्रिक कारें बेची, वहीं एमजी मोटर ने 5,829 यूनिट्स की बिक्री की। टाटा मोटर्स ने अब तक कुल 57,616 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं जो मार्केट का 53प्रतिशत हिस्सा है। एमजी मोटर ने 30,162 यूनिट्स बेची (28प्रतिशत मार्केट शेयर) और महिंद्रा ने 8,182 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं। सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। 2025 में भारत में 20 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं, जिसमें दोपहिया, तिपहिया और कारें शामिल है। देश में अब तक कुल 61 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर उतर चुके है। सवाल यह भी है कि डीजल और पैट्रोल गाड़ियों का क्या होगा? ये गाड़ियां पूरी तरह बंद तो नहीं होंगी लेकिन इनकी बिक्री में गिरावट जरूर आ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (एसआईएएम) के अनुसार, 2022-23 में डीजल कारों की बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई थी और 2025 में यह ट्रेंड और तेज हो गया है। कई शहरों में पुराने डीजल-पैट्रोल वाहनों पर सख्ती बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का खेल भी बढ़ गया है। अब गाड़ियों में स्मार्ट फीचर्स, ऑटोमैटिक ड्राइव, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। कंपनियां सिर्फ फ्यूल टाइप नहीं, बल्कि पूरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस बदलने पर ध्यान दे रही हैं। बैटरी की क्वालिटी, चार्जिंग स्पीड और रेंज में भी लगातार सुधार हो रहा है। लोग अब सिर्फ सस्ती गाड़ी नहीं, बल्कि स्मार्ट, इको-फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी गाड़ी चाहते हैं। युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक है और इलेक्ट्रिक कारों को स्टेटस सिंबल भी मानती है। इलेक्ट्रिक वाहन से उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण पैट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में कम होता है। बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फाइनेंसिंग और सब्सिडी के विकल्प भी बढ़ गए हैं जिससे खरीदना आसान हो गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत में बिकने वाली हर 10 में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई नौकरियां, नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल देखने को मिलेंगे।

पैट्रोल पंप की जगह चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे और गाड़ियों की सर्विसिंग भी बदल जाएगी। कुल मिलाकर, 2025 में डीजल-पैट्रोल गाड़ियां पूरी तरह आउट नहीं होंगी लेकिन उनका दबदबा जरूर कम हो जाएगा।

आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों की बाढ़ के साथ-साथ ऑटोमोबाइल का पूरा खेल ही बदलने वाला है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में हो रही वृद्धि भारतीय वाहन उद्योग और सरकार दोनों के लिए चुनौतियां भी ला रही है।

ट्रम्प की दादागिरी और भारत

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद 1991 तक भारत ने जो भी बहुआयामी तरक्की की वह अमेरिका के सहयोग के बिना ही की। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इन परिस्थितियों में अन्तर आया और भारत ने अमेरिका की तरफ भी देखना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप 2024 आते-आते भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी आर्थिक व सैनिक सहयोग बढ़ा। मगर इसका मतलब यह नहीं निकलता कि भारत अमेरिका की कृपा पर निर्भर होता चला गया। 1991 में भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण शुरू किये जाने के बाद भारत का विशाल बाजार अमेरिका के लिए आकर्षण का केन्द्र बना और अमेरिका भारत के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का स्थान। मगर अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यदि यह सोच रहे हैं कि वह भारतीय आयातित माल पर 50 प्रतिशत सीमा शुल्क लगा कर भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं तो बहुत बड़ी गलती पर हैं। भारत तब भी नहीं झुका था जब 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने पीएल-480 के तहत भारत को अन्न देना बन्द कर दिया था। पाकिस्तान ने यह युद्ध पूरी तरह अमेरिकी हथियारों के मार्फत लड़ा था। इसके बावजूद उसको जबर्दस्त शिकस्त हुई थी। इसके बाद 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच बंगलादेश युद्ध हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इस तरह पराजय दी कि पूरा पाकिस्तान बीच से अलग हो गया और इसके दो टुकड़े हो गये। एक टुकड़ा अब बंगलादेश कहलाता है। इन दोनों युद्धों में अमेरिका पाकिस्तान की तरफ खड़ा रहा और भारत को धमकाने का काम करता रहा परन्तु भारत ने अपनी शर्तों पर दोनों युद्धों को रोका परन्तु अब ट्रम्प कह रहे हैं कि विगत मई महीने में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिन्दूर शुरू करके जो संक्षिप्त युद्ध लड़ा उसका विराम उनकी मध्यस्थता के कारण ही हुआ। ट्रम्प ने 35वीं बार ऐसा दावा किया है कि विगत दस मई को उनके हस्तक्षेप की वजह से ही भारत-पाक के बीच युद्ध विराम हुआ। ट्रम्प यह कहते-कहते यह भी कह गये कि उन्होंने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत की और पाकिस्तानी हुक्मरानों से भी बात की और चेतावनी दी कि वे दोनों परमाणु युद्ध की तरफ अग्रसर न हों और 24 घंटे के भीतर युद्ध रोक दें। ट्रम्प का दावा है कि उनके हस्तक्षेप करने और यह कहने के बाद कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह दोनों देशों के माल पर इतना शुल्क लगा देंगे कि दोनों का सिर घूमने लगेगा। पहले तो ट्रम्प की यह भाषा कूटनीतिक मर्यादाओं के एकदम विरुद्ध है। दूसरे प्रधानमन्त्री मोदी संसद के पटल पर यह कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिन्दूर पर उनकी विश्व के किसी भी नेता से किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई और भारत ने युद्ध विराम पाकिस्तान की प्रार्थना पर किया। सवाल यह है कि ट्रम्प बार-बार यह क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ही भारत-पाक संघर्ष को रुकवाया? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही है कि वह विश्व शान्ति के लिए नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं क्योंकि ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में चल रहे अन्तर्देशीय संघर्षों को रुकवाने में सात बार सफलता हासिल की। दूसरा यह कि वह अपने देश अमेरिका के लोगों की ही अपने बारे में उपजी अवधारणा को सही करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को सन्देश देना चाहते हैं कि अमेरिका विश्व शान्ति के लिए समर्पित देश है।

प्रदेश में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 14.15 लाख युवाओं को दिया गया प्रशिक्षण व 5.50 लाख हुए सेवायोजित

उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा दिव्यांगों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालित कराये गये है। प्रशिक्षण में उद्योगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 227 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे व्यवसायों में से 52 व्यवसायों की 17,156 सीटों को ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (वै) के अन्तर्गत 03 से 06 माह का प्रशिक्षण अनुबन्धित किया गया है। प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप योजना/अप्रेन्टिसशिप योजना की ब्रान्डिंग करते हुये अधिक से अधिक युवाओं को भत्ते के साथ उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण उद्योगों में केन्द्र सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है एवं योजना के प्रोत्साहन हेतु एन0ए0पी0एस0 लागू करते हुये सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा प्रदान की गयी वृत्तिका के सापेक्ष 25 प्रतिशत (अधिकतम 1500/- प्रशिक्षार्थी प्रति माह) की प्रतिपूर्ति की जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अप्रेन्टिस प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रू0 1000/- प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अनेकों योजनायें संचालित कर उन्हें रोजगार से लगा रहे है। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाते हुए 'सबको हुनर, सबको काम' की नीति पर चलते हुए प्रदेश सरकार युवाओं/युवतियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही है। प्रदेश के बहुत से युवक/युवतियाँ शिक्षित तो होते है, किन्तु बिना किसी हुनर, कौशल के वे रोजगार से नहीं लग पाते है। प्रदेश सरकार उन्हें रोजगार से लगाने के लिए कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाती है और सम्बन्धित ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें स्वयं का बिजनेस, उद्यम स्थापित करने के लिए सहयोग एवं सरकारी/निजी क्षेत्र में सेवायोजित कराती है। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि वह उ0प्र0 का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 35 वर्ष की होना चाहिए। कुछ ट्रेड्स में आयु में शिथिलता है। प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदक को आवेदन ऑनलाइन भरते समय आधार कार्ड, निवास, आयु, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण, बैंक खाता नम्बर, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नम्बर आदि संलग्न करना होता है। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या को बढ़ाकर 324 किया गया है, जिससे वर्तमान में प्रवेशित सीटों की संख्या 1.84 लाख हो गयी है। अप्रेन्टिसशिप योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 69 हजार से अधिक युवाओं को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 08 वर्षों में 14.15 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 5.40 लाख युवाओं को सेवायोजन भी प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एन0एस0डी0सी0) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्वालिफिकेशन पैक्स/नेशनल आक्यूपेशनल स्टैण्डर्ड आधारित कुल 38 सेक्टर्स से 2750 से अधिक पाठ्यक्रम अनुमन्य किये गये है। वर्तमान में 452 निजी प्रशिक्षण प्रदाता, 334 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता और 25 फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता मिशन, 34 दिव्यांग प्रशिक्षण प्रदाता, 268 स्टार्ट-अप प्रशिक्षण प्रदाता तथा 10 एन0एस0डी0सी0 तथा एस0एस0सी0 प्रशिक्षण प्रदाता उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ आबद्ध किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत 415 प्रशिक्षण को भी अनुबन्धित किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक 01 ट्रिलियन डालर के स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से मैन पॉवर तैयार किये जा रहे है। यू0पी0जी0आई0एस0 2023 में विभाग हेतु 71 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे रू0 7031 करोड़ की धनराशि का निवेश आगामी वर्षों में होने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा स्कूली छात्र व छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट प्रवीण प्रारम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकाधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराये जाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अवार्डिंग बाडी की मान्यता प्राप्त करा कर अपने माँगपरक पाठ्यक्रम तैयार करने, मूल्यांकन व प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया गया है। राजकीय आई0टी0आई0 में इन्डस्ट्री 4.0 की अपेक्षाओं के अनुरूप अभिनव ट्रेड्स यथा ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया गया है। इसके साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी व सेवाक्षेत्र यथा इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी तथा लाजिस्टिक्स से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये आई0बी0एम0, टी0सी0एस0 तथा फ्लिपकार्ट जैसी कम्पनियों के साथ अनुबंध किया गया है। उद्योगों की माँग एवं इन्डस्ट्री 4.0 की आकांक्षाओं के अनुसार एवं सेवायोजकता के दृष्टिगत टीटीएल एवं उनके कन्सोर्टियम द्वारा सी0एस0आर0 के सहयोग से 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं 01 प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में कौशलम केन्द्र की स्थापना की गयी जिसमें 11 दीर्घकालीन न्यू एज कोर्स एवं 23 शार्ट टर्म कोर्सेस का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में 11,000 से अधिक प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षणरत है। इस परियोजना में रू0 4,282 करोड़ की धनराशि का निवेश किया गया है। शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0आई0टी0एस0) के अन्तर्गत प्रादेशिक स्टाफ शिक्षण एवं शोध केन्द्र (आई0टी0ओ0टी0) लखनऊ में संचालित 06 व्यवसायों को बढ़ाकर 10 व्यवसायों का कराया जा रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 39 हजार से अधिक प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों व एम0एस0एम0ई0 में प्रथम बार 07 से 15 दिवस की ऑन-जॉब ट्रेनिंग कराई गई है। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा दिव्यांगों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालित कराये गये है। प्रशिक्षण में उद्योगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 227 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हो रहे व्यवसायों में से 52 व्यवसायों की 17,156 सीटों को ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (वै) के अन्तर्गत 03 से 06 माह का प्रशिक्षण अनुबन्धित किया गया है। प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप योजना/अप्रेन्टिसशिप योजना की ब्रान्डिंग करते हुये अधिक से अधिक युवाओं को भत्ते के साथ उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण उद्योगों में केन्द्र सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है

एवं योजना के प्रोत्साहन हेतु एन0ए0पी0एस0 लागू करते हुये सम्बन्धित अधिष्ठान द्वारा प्रदान की गयी वृत्तिका के सापेक्ष 25 प्रतिशत (अधिकतम 1500/- प्रशिक्षार्थी प्रति माह) की प्रतिपूर्ति की जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अप्रेन्टिस प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रू0 1000/- प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह की प्रतिपूर्ति की जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पिछले 05 वर्षों में 05 पुरस्कार प्राप्त हुये है, जिनमें एसोचैम द्वारा वर्ष 2018-19 में बेस्ट स्टेट इन स्किलिंग की गोल्ड ट्रॉफी, वर्ष 2020-21 में इलेट्स द्वारा 17वीं वर्ल्ड एजूकेशन समिट, 2020 में कोर्स राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ऑन लाइन लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेश के 50 हजार छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्नीशन स्काच ग्रुप द्वारा स्किल इनीशिएटिव्स के लिये गोल्ड सर्टीफिकेट तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा ई-गवर्नेन्स श्रेणी में एवार्ड ऑफ एप्रीसिएशन सम्मिलित है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साथ पैपतनगा एस. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2018/...)

बीएसए नें प्राथमिक विद्यालय खुदरा एवं रहसू का किया औचक निरीक्षण

पडरौना, कुशीनगर।

बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ रामजियावन मौर्य ने प्राथमिक विद्यालय खुदरा एवं रहसू का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय खुदरा में प्रधानाध्यापक संजीव कुमार एवं सहायक अध्यापिका रुकैया उपस्थित मिली। बच्चों का पठन-पाठन चल रहा था एवं मिड डे मील में तहरी बनी हुई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मौर्य यहां बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता भी परखी और छोटे-छोटे बच्चों से कई प्रश्न किए जिनका छात्रों के द्वारा उत्तर दिया गया। साफ सफाई पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संतोष व्यक्त किया,जबकि कई कमरों के टूटे हुए फर्श के मरम्मत करने के लिए स्वयं के स्तर से प्रयास करने का विश्वास दिलाया तथा प्रधानाध्यापक को ग्राम प्रधान से संपर्क कर इस समस्या के समाधान का भी सुझाव दिया। बीएसए ने छात्र संख्या को और ठीक करने तथा बच्चों के गणवेश के लिए अभिभावकों से संपर्क कर खाते में भेजे गए पैसे से खरीदारी करने के लिए आग्रह करने को कहा। वही रहसू में अकेली शिक्षामित्र शालिनी के द्वारा बच्चों का पठन-पाठन कार्य संपन्न कराया जा रहा था। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मौर्य ने जब इसकी जानकारी मांगी तो पता चला कि अध्यापिका मैटरनिटी लीव पर गई हुई हैं। बीएसए डॉक्टर मौर्य नें एबीएसए पडरौना से बात कर विद्यालय पर एक शिक्षक तत्काल प्रभाव से तैनात करने के निर्देश दिए। विद्यालय के पुराने कमरों में साफ सफाई को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। छात्रों की संख्या पर भी चिंता व्यक्त की गई और गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ छात्र संख्या और बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा गया। बीएसए नें शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी के लिए बच्चों से प्रश्न किए जिसका बच्चों ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने संबंधित ग्राम प्रधान से संपर्क कर साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया।

ओवरलोडिंग, नशे में ड्राइविंग और लापरवाही पर लगाम, डीएम-एसपी ने कसी नकेल

*विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक में बनी रणनीति

*ओवरलोडिंग और पार्ट टाइम ड्राइवरों पर रोक

देवरिया।कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता विधायक रुद्रपुर जय प्रकाश निषाद ने की। बैठक में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, एमएलसी प्रतिनिधि समेत कई विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह बैठक बेहद गंभीर और निर्णायक साबित हुई। विधायक जय प्रकाश निषाद ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय बसों में निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसी भी वाहन को पार्ट टाइम ड्राइवर से नहीं चलाया जाएगा। परिचालक और चालक दोनों अनिवार्य रूप से वर्दी में रहेंगे और विद्यालय प्रबंधन समय-समय पर उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बैठक करे। विधायक ने यह भी कहा कि वैनों में अतिरिक्त सीटें लगाने की कुप्रथा पूरी तरह बंद होनी चाहिए। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने निर्देश दिया कि जिले के सभी विद्यालय प्रबंधक अपने-अपने वाहनों का फिटनेस कैंप में परीक्षण कराएँ।

हर वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएँ। डीएम ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था और वाहनों की नियमित सर्विसिंग की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस विद्यालय वाहनों की नियमित चेकिंग करेगी और अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ताकि वे भी निगरानी में सहयोग कर सकें। बैठक में यह भी तय हुआ कि समय-समय पर अभिभावकों से फीडबैक लिया जाएगा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी भी विद्यालय द्वारा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खुशबू जायसवाल को सूरापुर महोत्सव में किया गया सम्मानित

शाहगंज, जौनपुर।

नगर की मशहूर समाजसेविका निहारिका ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर खुशबू जायसवाल को हर सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये सूरापुर महोत्सव के विशाल मंच पर सम्मानित किया गया। बताते चलें कि जिस मंच पर सभी पुरुष वर्ग को सम्मानित किया गया उसी मंच पर शाहगंज नगर की एक अकेली महिला जो आज अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम से एक सफल बिजनेस वूमेन और एक समाजसेविका, सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बनाने वाली ऐसी महिला खुशबू जायसवाल को सूरापुर महोत्सव में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक गोलू अग्रहरि ने खुशबू जायसवाल को बड़ी बहन का दर्जा देते हुए कहा कि दीदी आपके ऊपर जैसे श्याम बाबा का आशीर्वाद है उसी तरह से आप भी अपना आशीर्वाद अपने छोटे भाई पर बना कर रखिएगा। इस अवसर पर मनोज अग्रहरि, अरविंद अग्रहरि, घनश्याम अग्रहरि, विशाल अग्रहरि, ऋषिराज जायसवाल आदि शामिल रहे।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ

कुशीनगर।

मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस-2025 के अवसर पर वृहद खेल एवं फिटनेश क्रिया कलापों के अन्तर्गत दिनांक 29 अगस्त, 2025 को जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम कुशीनगर में 14 वर्षीय जिला स्तरीय बालक हॉकी एवं जूनियर आयु वर्ग बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता एवं सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन कर बालक फुटबाल जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं जनपद में संचालित खेलों इण्डिया द्वारा जनपद स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता कराया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि विजय कुमार दूबे सांसद कुशीनगर एवं विशिष्ट अतिथि महेन्द्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी, कुशीनगर व सुरेन्द्र कुशवाहा देवरिया सांसद प्रतिनिधिउपस्थित रहें।

इस अवसर पर वरूण राय, चिन्टु शुक्ला, सदाशिव मणि त्रिपाठी, सूर्यप्रकाश राय, पीयूष कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, राकेश कुमार, उपायुक्त श्रम रोजगार, श्रवण कुमार गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक, डॉ0 रामजियावन मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर, मनीष कुमार गुप्ता, एन0आई0सी0 कुशीनगर, सुनील कुमार यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी कुशीनगर, सचिन कुमार, जिला युवा अधिकारी कुशीनगर एवं जिला खेल कार्यालय, कुशीनगर साथ ही विभिन्न खेलों/ स्कूलों/ कालेजों के खिलाड़ी उपस्थित थें।

सर्व प्रथम मुख्य अतिथि एवं अतिथिगण द्वारा मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर पुष्पार्चन किया गया तदोपरान्त् मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के द्वारा प्रदेश स्तर पर खेल दिवस सम्बन्धित कार्यक्रमों के शुभारम्भ का एल0ई0डी0 स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया जिसको अवलोकन स्टेडियम कुशीनगर में उपस्थित मुख्य अतिथि, अतिथिगण, खिलाड़ियों एवं छात्र/ छात्राओं नें किया। मुख्य अतिथि ने विजेता/ उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया।

14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता

प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला स्टेडियम-ए0 बनाम ध्यानचंद हॉकी क्लब के बीच हुआ जिसमें स्टेडियम-ए0 4-0 से विजयी रही। पहला सेमी फाइनल मैच स्टेडियम-ए0 बनाम भिस्वा सरकारी के बीच हुआ जिसमें स्टेडियम-ए0 3-0 से विजयी रही। दूसरा सेमी फाइनल मैच ध्यानचंद हॉकी क्लब बनाम श्रीमती लाची देवी समाज कल्याण इण्टर कालेज जटहा के बीच हुआ जिसमेंध्यानचंद हॉकी क्लब 1-0 से विजयी रही। प्रथम मैच स्टेडियम-ए0 बनाम शाकुन्तल इण्टर कालेज के बीच हुआ जिसमें स्टेडियम-ए0 4-0 विजयी रही। द्वितीय मैच एस0एस0 पब्लिक स्कूल बनाम भिस्वा सरकारी के बीच हुआ जिसमें भिस्वा सरकारी 1-0 से विजयी रही। तृतीय मैच ध्यानचंद हॉकी क्लब बनाम स्टेडियम-बी0 के बीच हुआ जिसमें ध्यानचंद हॉकी क्लब 2-1 से विजयी रही।

खेल विभाग एवं मेरा युवा भारत केन्द्र, कुशीनगर (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार) के तात्वावधान में 14 वर्षीय बालिका हॉकी की भी प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसमें स्टेडियम-ए0 बनाम स्टेडियम-बी0 के बीच मैच हुआ जिसमें स्टेडियम-बी0- 05 गोल कर विजेता रही स्टेडियम-बी0- 02 गोल कर उपविजेता रही। प्रतियोगिता के सफल संचालन में गुड्डू गुप्ता, श्रीमती ममता भारती, अनिल मिश्रा धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आदि उपस्थित रहे। अन्त में रवि कुमार निषाद जिला क्रीड़ाधिकारी कुशीनगर ने मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि, विजेता, उपविजेता खिलाड़ियों एवं मिडिया इलेक्ट्रानिक के प्रति आभार व्यक्त किया।

लायंस क्लब क्षितिज का 6वां स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न

जौनपुर।

लायंस क्लब जौनपुर क्षितिज का 6वां स्थापना दिवस समारोह शहर के एक होटल में धूमधाम से मनाया गया। संस्थाध्यक्ष अतुल सिंह की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत सरिता मिगलानी द्वारा ध्वज वंदना से हुई। इसके बाद संस्थापक अध्यक्ष लायन शशांक सिंह रानू,वर्तमान अध्यक्ष लायन अतुल सिंह, पूर्व अध्यक्ष लायन दिलीप सिंह, जयकृष्ण साहू, विष्णु सहाय, धर्मेंद्र सेठ, निवर्तमान अध्यक्ष लायन प्रदीप सिंह, सचिव लायन अजीत सोनकर, कोषाध्यक्ष लायन सुनील कन्नौजिया व अन्य चार्टर सदस्यों ने दीप प्रज्ज्वलित, पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्थापक सदस्यों को अंगवस्त्रम, माल्यार्पण और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। लायन अंजनी प्रजापति द्वारा विभिन्न प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं कराई गईं, जिनमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। संस्थापक अध्यक्ष शशांक सिंह रानू ने संस्था की स्थापना से जुड़े संस्मरण साझा किए और संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सेवा कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष सुनील कन्नौजिया ने गुड पे सदस्यों को गुड पे अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। संस्थाध्यक्ष अतुल सिंह ने सभी सदस्यों को गिफ्ट प्रदान किया व संस्था में विशेष सहयोग और सक्रिय भागीदारी के लिए लायन संजय कुमार गुप्ता को प्राउड मेंबर पिन से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि आगामी दिनों में राजमहल में बिज़नेस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा जो जौनपुर का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। समारोह में उपाध्यक्ष कौशल त्रिपाठी, सर्वेश जायसवाल, आशीष चौरसिया, आशीष सिंह, देवआनंद, संजय जायसवाल, नीरज कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, विशाल बरनवाल, देवेंद्र सिंह, डॉ. प्रशांत द्विवेदी, डॉ. चंदन नाथ गुप्ता, राजीव गुप्ता, जगन्नाथ मोदनवाल, दिलीप जायसवाल, रत्नेश जी, देवेश जी, ज्ञानेंद्र सिंह, संजय गुप्ता, शरद टण्डन, अभिषेक, रत्नेश शर्मा आदि उपस्थित रहीं। महिला सदस्यों में यवनिका सिंह, चेतना साहू, सीमा सहाय, किरण सेठ, नीतू सिंह, आराधना सिंह, सुषमा सोनकर, चांदनी साहू, मृदुला सिंह, रेखा सिंह, सीमा चक्रवाल, एकता बरनवाल, शिल्की श्रीवास्तव, दीपशिखा चौरसिया, डॉ. आकांक्षा द्विवेदी, सुधा बैंकर, उषा मोदनवाल, रिंकी श्रीवास्तव, निशा कनौजिया, नीलम जायसवाल, बबीता जायसवाल, शिल्पी जायसवाल, मीना गुप्ता, उमा गुप्ता, सुमन गुप्ता, पूजा आदि शामिल रहीं। कार्यक्रम का सफल संचालन संजय गुप्ता और अंजनी प्रजापति ने किया। संयोजन अभिषेक गुप्ता शम्मी और मोहम्मद हाफ़िज़ शाह ने किया। अंत में अध्यक्ष अतुल सिंह ने सभी अतिथियों और सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

महिला वकीलों के लिए POSH एक्ट लागू न करने पर सरकार-बीसीआई को नोटिस; शहरी बेघर आश्रय बंद करने की होगी जांच

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में पंजीकृत महिला वकीलों के लिए कार्यस्थल पर POSH एक्ट लागू करने से जुड़ी याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अदालत जाने के अधिकार के तहत हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका कैसे दायर की जा सकती है? 7 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि POSH कानून केवल नियोक्ता-कर्मचारी संबंध में ही लागू होता है। इसलिए महिला वकील इसके दायरे में नहीं आतीं। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना को हटाने पर सहमति व्यक्त की। शीर्ष अदालत अधिवक्ता और लेखिका सीमा जोशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम को राज्य बार काउंसिल/बार एसोसिएशन में नामांकित महिला अधिवक्ताओं पर लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। अधिवक्ता रितिका वोहरा और नमन जोशी के माध्यम से दायर याचिका में महिला अधिवक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए POSH अधिनियम के तहत आंतरिक समितियों का गठन/जारी रखने के निर्देश देने की भी मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल या बार एसोसिएशनों पर POSH अधिनियम की प्रयोज्यता के मुद्दे पर स्पष्ट मिसाल के अभाव में भारत में महिला वकीलों को राज्यों में असमान संरक्षण का खतरा है। कानून का मूल उद्देश्य और डिजाइन इन अधिकारों को प्रभावी बनाना है और कोई भी व्याख्या जो महिला अधिवक्ताओं को इसके संरक्षण से बाहर रखती है, वह उस संविधानिक उद्देश्य के विपरीत है जिसे अधिनियम पूरा करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को डीएमआरसी के काम के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शहरी बेघर आश्रयों के स्थानांतरण का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। शीर्ष अदालत ईआर कुमार की 2003 की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के निर्माण कार्य के कारण राजधानी के आनंद विहार और सराय काले खां में आठ मौजूदा आश्रय गृहों को बंद किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ से याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इन आश्रय स्थलों के बंद होने से सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। वकील ने बताया कि छह आश्रय स्थलों को पहले ही बंद किया जा चुका है। अब प्राधिकारी सराय काले खां और आनंद विहार स्थित आठ अन्य आश्रय स्थलों को भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। वहां वर्तमान में एक हजार से अधिक बेघर लोग रह रहे हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने दिल्ली मेट्रो से संबंधित चल रहे निर्माण कार्य के लिए इन आश्रयों को स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है.

राहुल की यात्रा में पीएम को गाली, बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े

पटना। दरभंगा में इंडिया ब्लॉक की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बिहार के पटना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पथराव किया गया। बिहार के मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। नवीन ने एएनआई से कहा कि बिहार का हर बेटा एक मां के अपमान के लिए कांग्रेस को करारा जवाब देगा। हम इसका बदला लेंगे। वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता आशुतोष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह झड़प सरकार की मिलीभगत से हुई है। आशुतोष ने कहा कि करारा जवाब दिया जाएगा। यह सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बस यही बचा है इनका (भाजपा का) काम। सरकार में रहते हुए ये इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी लड़ाई मतदाताओं के लिए है। हम किसी भी सूरत में यह स्वीकार नहीं करेंगे कि गुजरात से लाकर यहां मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है और बिहार के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। यह घटना इंटरनेट पर एक कथित वीडियो के बाद हुई है जिसमें आरोपी को इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच, भाजपा नेताओं ने कथित अपमानजनक भाषा के लिए विपक्ष की मतदाता अधिकार यात्रा की आलोचना की है।

> राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है – हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते।

हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड, 11 मौतें

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग सहित 4 जिलों में बादल फटा; 5 की जान गई, 3 लापता

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो गई है। मृतकों में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। दो लोगों की अभी पहचान नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार, लोगों की मौतें पहाड़ से पत्थर गिरने और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। भरमौर में करीब 3 हजार मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले सप्ताह लैंडस्लाइड में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 9 लापता हो गए थे। दूसरी तरफ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जिले में गुरुवार रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। तीन लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि लैंडस्लाइड के कारण लगभग 30-40 परिवार मलबे के ढेर में दब गए और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बागेश्वर जिले के पौसारी में रात भर बारिश से दो लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग के जखोली में मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई। 4 नेपाली और 4 स्थानीय सहित 8 मजदूर मलबे में दबे हैं। रुद्रप्रयाग में मलबे में फंसे 70 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। चमोली में भी कई परिवारों के मलबे में फंसे होने की आशंका है।

यूपी के सभी मंडल में खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज - सीएम योगी

- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवांवित करने वाले 88 खिलाड़ी पुरस्कृत
- मुख्यमंत्री ने पूर्व ओलंपियन को भी किया सम्मानित
- यूपी के खिलाड़ियों को भी मिलेगा विदेश में ट्रेनिंग का मौका
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में ही नौकरी

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर उनको नमन करने के साथ हॉकी के जादूगर के प्रति अपने प्रेम को भी दर्शाया। उन्होंने पद्मश्री मोहम्मद शाहिद स्टेडियम के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर हॉकी पर हाथ आजमाने के साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवांवित करने वाले 88 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व ओलंपियन को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयंत खंड के मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ी के लिए माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। सरकार अब हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेगा और सभी मंडल में कॉलेज एक्सीलेंस सेंटर की भी स्थापना करेगी। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धमक बढ़ रही है, हमें उसको बरकरार रखना होगा। इसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजना होगा तो हम भेजेंगे। खेल विभाग से खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश में आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देश और प्रदेश खेल की नई नीति लागू कर दी गई है। इससे नए खिलाड़ियों को अच्छे मंच मिलेंगे। इनको अच्छे प्रशिक्षकों के साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि प्रदेश के हर कमिश्नरी में एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल में पारंगत होने का अवसर मिल सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में ही नौकरी देने के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर इंतजाम किया है। ग्रेड ए के पदों पर प्रदेश के प्रतिभावान कुशल खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए सभी विभागों में दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ विभिन्न विभागों में नौकरी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश तो मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि है। उनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण किया है। उन्होंने कहा कि जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है तो हर भारतीय के मन में हॉकी स्टिक की छवि उभर आती है। हॉकी के जादूगर ने अपने बेहतरीन खेल से दुनिया को अपना प्रशंसक बना लिया था।

मणिपुर को पूरी तरह अपने हाल पर छोड़ दिया
पीएम मोदी के विदेश दौरे पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा और आगामी चीन यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से अपने हाथ खींच लिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री विभिन्न देशों की यात्रा करते रहे, लेकिन मणिपुर के लंबे समय से पीड़ित लोग अपने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उनकी यात्रा का इंतजार कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री ने सीधे और हठपूर्वक अस्वीकार कर दिया था। अपने पोस्ट में आगे, कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मोटे तौर पर उनकी अपनी शर्तों पर। पोस्ट में लिखा है कि अवसर उड़ान भरने वाले (और उससे भी ज्यादा बार झूठ बोलने वाले) प्रधानमंत्री जापान और चीन की यात्रा पर हैं। उनकी चीन यात्रा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। हमें चीन के साथ संबंध सामान्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ड्ड मोटे तौर पर उनकी शर्तों पर, और चीन भारत-अमेरिका संबंधों में आई गिरावट का भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी जिसका खुलासा खुद हमारे अपने सैन्य प्रतिष्ठान ने किया था को भुला दिया गया है। 19 जून, 2020 को प्रधानमंत्री का असाधारण रूप से विचित्र बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि -न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है-, ने हमारी बातचीत की क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने हमारे पास पैंतरेबाज़ी करने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ी और यह यात्रा, अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करने में विफलता के बावजूद, उस कुख्यात और कायरतापूर्ण क्लीन चिट का अपरिहार्य परिणाम है। पोस्ट में आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री के विदेश चले जाने के बावजूद, मणिपुर के लंबे समय से पीड़ित लोग मई 2023 के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उनकी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री राज्य, उसके राजनीतिक दलों और नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और स्वयं लोगों से बातचीत करने से साफ़ और हठपूर्वक इनकार कर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर से अपने हाथ खींच लिए हैं - जो केंद्रीय गृह मंत्री की भूल का एक दुखद प्रमाण है।

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट का महिलाओं के लिए बड़ा फैसला; रोजगार के लिए मिला सीधा ऑफर

पटना।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब इसी दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल राज्य के विकास में योगदान दे रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट की बैठक में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर परिवार की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना की प्रमुख बातें

प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये प्रथम किस्त के रूप में दिए जाएंगे।

आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग करेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।

सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि का हस्तांतरण शुरू होगा।

रोजगार शुरू करने के छह माह बाद महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।

महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे।

रोजगार और सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही राज्य के भीतर ही बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को मजबूरी में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी- संजय राउत

मुंबई। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है. इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बीजेपी को ही घेरा है. उद्धव गुट के नेता ने पीएम मोदी के लिए किए गए अपशब्दों को लेकर पूछे गए सवाल पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. जब उनसे पूछा गया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गालियां दी जा रही है. इस पर संजय राउत ने कहा, कौन दे रहा है गाली? कार्यकर्ता कोई देता होगा लेकिन बीजेपी के लोग भी अंदर छोड़े होते हैं. किसी अच्छे काम को बदनाम करने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं. महाराष्ट्र में हमारा अनुभव है. ये लोग किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकते हैं. ये उनके ही लोग होंगे.

वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन भी स्थगित

जम्मू।

कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी स्थगित रही, क्योंकि भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह भूस्खलन हुआ। इस व्यवधान के कारण कई श्रद्धालु फंस गए और कई को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। प्रभावित लोगों में से, श्रद्धालुओं ने अपना दुख व्यक्त किया और घायलों व मृतकों के लिए प्रार्थना की। एएनआई से बात करते हुए, सुशील सिंह नाम के एक श्रद्धालु ने कहा कि हम लगभग 18-20 लोग वैष्णो देवी यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। हम हर साल ऐसा करते हैं। आज यहाँ हमारा तीसरा दिन है, और अभी तक हमें माँ के दर्शन नहीं हुए हैं। अब हम लौट रहे हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार, इसमें दो दिन लग सकते हैं, लेकिन यह निश्चित नहीं है... माँ घायलों को ठीक करें।

पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द के लिए माफी मांगें राहुल गांधी, कांग्रेस पर जमकर बरसे शाह

> शाह बोले- पीएम को जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा

गुवाहाटी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में शुक्रवार (29 अगस्त) को कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति शुरू कर दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों की सख्त आलोचना की. गृहमंत्री ने कहा कि आप जितना पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहोगे, कमल उतना ही ज्यादा ऊंचा खिलेगा. अमित शाह असम दौरे पर हैं. उन्होंने गुवाहाटी में राजभवन की नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र इकाई का उद्घाटन किया. अमित शाह ने कहा, इस मंच से राहुल गांधी ने जिस तरह से घृणा के निम्न स्तर की शुरुआत की है और पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द की हृदय से निंदा करता हूं. यह घृणा की राजनीति राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन को गर्त में ले जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी जब से पीएम बने हैं तब से सोनिया गांधी और ने क्या क्या कहा नहीं कहा. इस तरह की भाषा से आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या, बार-बार इनको हार का मुंह देखना पड़ा है, पर इनको समझ नहीं आता है. अमित शाह ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, आप जितना ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहेंगे, उतना ज्यादा कमल ऊंचा खिलेगा. राजनीति को अगर कोई प्रदूषित करे तो उससे देश कैसे सुरक्षित हो सकता है. देश अचंभित होकर इनके कृत्य को देख रहा है. सारी सीमाएं लांघी जा चुकी है. देश के लिए इनको जरूर माफी मांगनी चाहिए और इनको भगवान सद्बुद्धि दे. उन्होंने कहा, जब पूर्वोत्तर और असम का इतिहास लिखा जाएगा तो पीएम मोदी के ये 11 साल स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाएंगे. आज असम में तेजी से विकास हो रहा है. असम के विकास की गति हमेशा बनी रहेगी. हमने अंग्रेजों के बनाए कानूनों को रद्द किया है. आज हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है. 11 साल में मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए आमूल-चूल काम किया है.

जापान तकनीक- तो भारत टैलेंट का पावरहाउस : प्रधानमंत्री मोदी

- मोदी बोले-दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर
- जापानी पीएम ने कहा- भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक-दूसरे के लिए बने

पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला

टोक्यो। दो दिवसीय जापान दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-जापान आर्थिक फोरम में शिरकत की। यहां उन्होंने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले जापान में प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी के आगमन पर जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह भारत-जापान संयुक्त इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत-जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावरहाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावरहाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी से पहले जापान के पीएम इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक-दूसरे के लिए बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन जापानी भाषा के साथ शुरू किया। उन्होंने वहां की भाषा में लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावरहाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावरहाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, मैं आज सुबह ही टोक्यो पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी यात्रा की शुरुआत बिजनेस जगत के दिग्गजों के साथ हो रही है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है, जब मैं गुजरात में था तब भी और जब मैं दिल्ली आ गया तब भी। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप्स तक हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में 30 बिलियन डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्ट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व परिवर्तन से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है, नीति में में पारदर्शिता है, पूर्वानुमान की क्षमता है।

आज भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अहम अर्थव्यवस्था है। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने एक राष्ट्र, एक कर लागू किया था। अब और भी बड़े सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं। कुछ ही हफ्ते पहले हमारी संसद ने एक सरलीकृत आयकर प्रणाली को मंजूरी दी है। हालांकि, हमारे सुधार केवल कराधान से कहीं आगे तक जाते हैं। हमारे सुधार केवल कर प्रणाली तक सीमित नहीं हैं। हमने व्यापार करने में आसानी पर बल दिया है। व्यापार के लिए एकल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने कहा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्र पहले ही निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। अब हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी खोल रहे हैं। इन सुधारों के पीछे विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प निहित है। हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास और स्पष्ट रणनीति पर आधारित है। दुनिया ने इसे पहचाना है। आज दुनिया सिर्फ भारत पर नजर नहीं रख रही है, बल्कि भारत पर भरोसा कर रही है। एसएंडपी ग्लोबल ने दो दशक बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है। उन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है। हम साथ मिलकर वही मैजिक, बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमी-कन्डक्टर, शिप-बिल्डिंग और परमाणु ऊर्जा में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं- आइए, भारत में बनाएं, विश्व के लिए बनाएं। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कम्प्यूटिंग, बायोटेक और अंतरिक्ष में साहसिक और महत्वाकांक्षी कदम लिए हैं। जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है।